एक देश–एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

संसद के शीतकालीन सत्र में आएगा विधेयक, संविधान में होगा संशोधन

अगले कुछ महीनों के दौरान देशभर में लागू करने के उपायों पर होगी चर्चा

सत्ताधारी दल सहित 32 पार्टियां इसके पक्ष में, 15 दल विपक्ष में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव के बाद उभरे नए राजनीतिक समीकरणों के बीच एक देश–एक चुनाव को लेकर खड़े हो रहे सवालों से फिलहाल पर्दा उठा गया है। मोदी कैबिनेट ने एक देश–एक चुनाव पर बनी राम नाथ कोविन्द समिति की अनुशंसा को मंजूरी दे दी है। साथ ही संकेत दिया है कि सुधार के अपने एजेंडे से सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। समिति ने यह सिफारिश इसी वर्ष मार्च में की थी। माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लेकर विधेयक पेश किया जाएगा और इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा।

कैबिनेट के इस फैसले के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस, आप सहित कई विपक्षी दलों ने जहां इसे सिरे से खारिज किया है, वहीं भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने इसका स्वागत किया।

एक देश–एक चुनाव को लेकर कैबिनेट में लिए अहम फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे हैं। लेकिन इसके बाद विधानसभाओं के बीच में भंग होने से इनमें बदलाव आया। मौजूदा समय में स्थिति यह हो गई है कि हर समय देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते रहते हैं। इसका असर देश के विकास पर पड़ता है। इसे लेकर 2015 में संसदीय समिति ने भी अपनी सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले कई वर्षों से अलग–अलग मंचों के जरिये एक देश–एक चुनाव की बात मजबूती से उठाते रहे हैं। एक सवाल के जवाब में वैष्णव ने बताया कि संसद में जल्द ही इसे लेकर विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविन्द समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह बनाया जाएगा और अगले कुछ महीनों के दौरान इसे लागू करने के उपायों पर देशभर में चर्चा की जाएगी। इस दौरान सरकार इस पर आमसहमति बनाने की दिशा में काम करेगी। यह विषय ऐसा है जो देश को मजबूत बनाएगा। विपक्षी पार्टियां अब शायद अंदरूनी दबाव महसूस करेंगी क्योंकि समिति की परामर्श प्रक्रिया के दौरान 80 प्रतिशत लोगों खासकर युवाओं ने इसका काफी समर्थन किया था। फिलहाल तीन राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव लोकसभा चुनावों से छह महीने पहले होते हैं। जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, झारखंड और दिल्ली के चुनाव लोकसभा चुनाव से पांच–सात महीने बाद होते हैं। बाकी राज्यों में एक से तीन वर्ष के अंतराल में चुनाव होते हैं।

नई दिल्ली में बुधवार को कैबिनेट के निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। एएनआइ

> कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द जी की सराहना करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
>
> – नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

> यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वच्छ और वित्तीय रूप से कुशल चुनावों के माध्यम से देश के लोकतंत्र को मजबूत करने और संसाधनों के अधिक उत्पादक आवंटन के जरिये आर्थिक विकास को गति देने की 'लौह इच्छाशक्ति' को दर्शाता है।
>
> – अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

क्या होंगे लाभ

- देश को बार–बार चुनाव के भंवर में नहीं फंसना होगा।
- विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ेगी। अभी चुनाव के चलते नए कामकाज रुक जाते हैं।
- देश पर बार–बार के चुनावों के कारण वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
- केंद्र और राज्य के बीच कटुता की स्थिति नहीं बनेगी। अभी केंद्र में सत्ताधारी दल को राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान वहां के सत्ताधारी दल के कार्यों का खुला विरोध करना होता है।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

किसानों के लिए खोला खजाना : केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के हित में दो बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम–आशा) योजना को जारी रखा जाएगा। साथ ही रबी मौसम के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी को भी मंजूर कर लिया गया है। (पेज–3)

पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी : कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी मंजूरी दी। योजना पर कुल 79,156 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 56,333 करोड़ रुपये और राज्यों की हिस्सेदारी 22,823 करोड़ रुपये होगी। (पेज–3)

एक राष्ट्र, एक चुनाव के मुद्दे पर पक्ष हो या विपक्ष, दोनों खेमों के कई दलों ने साधी चुप्पी

एक राष्ट्र, एक चुनाव के मुद्दे पर राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने समाज के विभिन्न वर्गों से परामर्श किया था। इनमें 62 राजनीतिक दलों से भी राय मांगी गई थी। भाजपा, राजग की कई सहयोगी पार्टियों सहित 32 दलों ने सहमति जताई, जबकि कांग्रेस, तृकां, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, डीएमके, एआइएमआइएम, सीपीआइ (एम) समेत 15 दलों ने प्रस्ताव का विरोध किया। कुछ पार्टियों ने तटस्थता का भाव दिखाते हुए चुप्पी साधे रखी। तेदेपा, जम्मू–कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस, जद (एस), राजद, रालोद, झामुमो, राकांपा, बीआरएस व आइयूएमएल जैसे दलों ने समिति के बार–बार के अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

एक देश–एक चुनाव पर समिति की अहम सिफारिशें पेज>>5

अंतरिक्ष में लगेगी बड़ी छलांग, 2028 तक स्थापित होगा पहला स्टेशन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

चंद्रयान–3 की सफलता के बाद भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। जल्द ही अंतरिक्ष से जुड़े अपने चार और मिशनों को अंजाम देगा। इसमें अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला अंतरिक्ष स्टेशन भी शामिल है, जो दिसंबर, 2028 तक स्थापित हो जाएगा। इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। मौजूदा समय में अंतरिक्ष में दो ही स्टेशन हैं। इनमें पहला स्टेशन अमेरिका, रूस व यूरोपीय देशों के सहयोग से स्थापित है, जिसे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाता है, जबकि दूसरा स्टेशन चीन का है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े चार प्रमुख प्रस्तावों में मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अहम पहले अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और गगनयान फालो–आन मिशन शामिल है। इस पर कुल 20,193 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट ने इसके साथ चंद्रयान–4 मिशन को भी सहमति दे दी है। जो न सिर्फ चंद्रमा पर उतरेगा, बल्कि वहां से कुछ चीजें लेकर सुरक्षित भी लौटेगा। मिशन को अगले 36 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चंद्रयान–3 के बाद यह उस दिशा में एक बड़ा अभियान होगा। इस पर कुल 2,104 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

कैबिनेट ने अंतरिक्ष से जुड़े जिन अन्य मिशनों को मंजूरी दी है, उनमें वीनस (शुक्र) आर्बिटर मिशन है। जिसमें अंतरिक्ष यान वीनस की कक्षा में भेजा जाएगा। यह मिशन मार्च, 2028 में लांच होगा। इस पर करीब 1,200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मिशन के लिए अगले चरण का एक लांचिंग व्हीकल तैयार करने को भी मंजूरी दी गई है। इस पर करीब आठ हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसे अगले 96 महीनों में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले दिनों में इस नए लांचिंग व्हीकल से अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में आसानी होगी। गौरतलब है कि अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करने का एलान प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान–3 की सफलता के बाद ही कर दिया था।

20 हजार करोड़ रुपये से अधिक होंगे खर्च इस परियोजना पर

- चंद्रयान–4, वीनस आर्बिटर मिशन व नए लांचिंग व्हीकल को भी मंजूरी

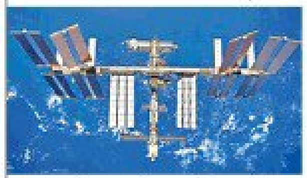

अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करने वाला तीसरा देश बनेगा भारत। प्रतीकात्मक

अंतरिक्ष में स्थापित दो स्टेशन

1. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन : यह अमेरिका, रूस सहित यूरोपीय देशों के सहयोग से पृथ्वी से 400 किमी की ऊंचाई पर स्थापित है। इसे 1998 में लांच किया गया था। अंतरिक्ष में भेजा गया यह सबसे बड़ा ढांचा है। मौजूदा समय में यहां कई देशों के अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं।

2. चीन का अंतरिक्ष स्टेशन : पृथ्वी से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में स्थापित है। यह वर्ष 2022 में भेजा गया था। इसमें भी मौजूदा समय में अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं।

भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को भेजा नोटिस

- कहा–परिस्थितियों में मूलभूत बदलाव होने से समझौते की समीक्षा जरूरी
- नदियों के जल वितरण पर सहयोग के लिए 1960 में हुई थी यह संधि

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजा है। भारत का कहना है कि परिस्थितियों में मूलभूत और अप्रत्याशित बदलाव हुए हैं, जिससे इस समझौते का पुनर्मूल्यांकन जरूरी हो गया है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को बताया कि यह नोटिस 30 अगस्त को सिंधु जल समझौते के अनुच्छेद 12 (3) के तहत भेजा गया है। नौ वर्षों तक चली बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ने 19 सितंबर, 1960 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे।

इस संधि का मकसद दोनों देशों के बीच बहने वाली विभिन्न नदियों के जल वितरण पर सहयोग और जानकारी का आदान–प्रदान करना है। भारत ने इस नोटिस में परिस्थितियों में आए मूलभूत और अप्रत्याशित बदलावों का जिक्र किया है, जैसे- जनसंख्या परिवर्तन, पर्यावरणीय मुद्दे और स्वच्छ ऊर्जा के विकास की जरूरत। इसके अलावा भारत ने सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव को भी समीक्षा का एक कारण बताया है।

सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में विश्व बैंक ने एक ही मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञ और आर्बिट्रेशन कोर्ट दोनों को एक साथ सक्रिय किया है। लेकिन भारत का कहना है कि विवाद को हल करने के लिए एक ही समय दो प्रक्रियाओं का उपयोग करना सिंधु जल संधि के प्रविधानों का उल्लंघन करता है। भारत तटस्थ विशेषज्ञ के माध्यम से समाधान पर जोर दे रहा है। साथ ही सरकारों के स्तर वार्ता शुरू करने का आह्वान किया है।

Cabinet nod for 'one nation, one election'

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Union Cabinet on Wednesday approved former President Ram Nath Kovind-led committee's report on the "one nation, one election" proposal months after the panel submitted its report to the government recommending a legally tenable mechanism to restore simultaneous elections.

Union minister Ashwini Vaishnaw said the report found widespread support for simultaneous polls and that the Cabinet approved it unanimously. He added recommendations of the panel will be discussed across India on various fora. "Implementation group will be formed to take forward recommendations of the Kovind panel on simultaneous polls," said Vaishnaw. "A number of parties have supported simultaneous polls. We will seek to create consensus over next few months."

The Kovind panel was mandated to study the existing framework and recommend amendments to the Constitution, the Representation of the People Act, etc needed for synchronised polls. It recommended simultaneous polls to the Lok Sabha and the assemblies as the first step. It then suggested the elections to municipalities and panchayats be synchronised with those for Lok Sabha and assemblies. This was proposed to be done in a way that polls to local bodies are held within 100 days of those to Lok Sabha and assemblies. The panel said implementing step one does not need ratification by the states.

The committee recommended an amendment to the Constitution to introduce the concepts of full and unexpired terms. It said the election held in case a House is dissolved sooner than its full term would be considered a mid-term poll. The panel added election held after the expiry of five years would be a general election. Simultaneous polls shall mean general elections for constituting the Lok Sabha and all the state assemblies together, it said.

"One nation, one election" was one of the key promises in the Bharatiya Janata Party (BJP)'s manifesto for the 2024 national elections.

In August, Prime Minister Narendra Modi urged political parties to help realise the goal of "one nation, one election", underlining frequent polls were a hurdle to India's progress. He referred to extensive consultations across the country on the issue and said all political parties have given their views. Modi said Kovind-led panel has submitted an excellent report.

"Frequent elections are creating hurdles in the progress of the nation. It has become easy to link any scheme or initiative with elections. There are elections somewhere every three to six months. Every work is linked to elections," Modi said in his address from the ramparts of the Red Fort on Independence Day.

He added the nation has to come forward for "one nation, one election".

Modi asked the parties to ensure that national resources are used for the common man. "We have to come forward to realise the dream of one nation one election."

India and Quad: A tale of collaboration

The upcoming summit will reinforce the awareness of Delhi's strategic options as it deals with its challenges and seeks to maximise its opportunities

Arun K Singh

The Quad summit to be held on September 21 in United States (US) president Joe Biden's hometown, Wilmington (Delaware), will be the sixth since the meetings at this level were initiated in March 2021 by the Biden administration, within months of taking over in January that year. Including the upcoming one, Biden would have hosted four when he leaves office — there were two virtual meetings, in March 2021 and 2022, and the first-ever in-person Quad summit in September 2021. Two intervening summit meetings were hosted by Japan (May 2022) and Australia (May 2023). It will be India's turn to host in 2025. The new US president and the incoming team will have to focus on a visit to India early in the term and explore additional deliverables and outcomes for the visit, providing continuity as the transition from the Biden administration takes place.

Biden hosting four summits is an attestation of the importance attached by the US to this framework for cooperation and coordination. It has also worked to India's advantage. The US is now more willing to partner with India in terms of technology. The two countries launched the pathbreaking Initiative on Critical and Emerging Technologies (iCET) in January 2023, which provides for cooperation in Artificial Intelligence (AI), quantum, biotechnology, semiconductors, space, and defence, among others. It has provided a cushion to handle disagreements on issues such as the Russia-Ukraine conflict. There was a proposal in the US Senate that India should be exempt from sanctions under the Countering American Adversaries through Sanctions Act (CAATSA) for major defence and other purchases from Russia because it is a member of Quad.

The significance and achievements of Quad today can be better understood if we recall the context in which it was first conceived, and the challenges it experienced. It had first come together in response to the 2004 tsunami in the Indian Ocean and aimed at coordinating humanitarian assistance and disaster relief (HADR) response by the four navies of the US, Japan, Australia, and India that had displayed capacity on the occasion. A meeting of Quad officials took place on the margins of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Regional Forum in the Philippines in 2007. Thereafter, it languished in the face of the sensitivity of some members, including Australia, to perceived opposition from China, with which they had strong trade and economic linkages. It was revived by the Donald Trump administration, which had made a pushback against China's predatory economic and trade policies and its unilateral assertiveness in the East and South China Seas and elsewhere, a major plank of its presidential campaign and subsequent policy. A meeting of officials of the revived Quad took place in 2017 on the sidelines of the East Asia Summit. After several meetings at this level, it was raised to foreign minister-level meetings in September 2019. Members have now met eight times at this level, twice in the Trump administration and six times since 2021.

It should be recognised that Quad is one of several frameworks of cooperation that US is involved with in the Indo-Pacific. It has treaty relationships with Japan, Australia, New Zealand, South Korea, and the Philippines. It launched AUKUS with Australia and the United Kingdom in 2021, to provide Australia with capacity for nuclear propulsion conventionally armed submarines, and high-level defence technologies. It has also initiated a quadrilateral arrangement with the Philippines, Japan and Australia, focusing more on security responses to China's actions in the East and South China Seas.

Quad, however, has its own significance. It has enabled the US to explore plurilateral convergences with India beyond the strengths of the bilateral relationship. From the Indian perspective, it has catalysed greater willingness in the US to do more with India bilaterally. Beyond the iCET, the US has now authorised technology transfer to India of GE F414 jet engines, which had been difficult earlier. Japan and Australia are also willing to do more with India bilaterally, because of Quad and the enhanced US willingness.

Quad has enabled the US to explore plurilateral convergences with India beyond the strengths of the bilateral relationship AFP

In addition to strengthening their relationships, Quad countries need to show positive benefits to other countries in the region flowing from the partnership. Otherwise, they would look at the Quad with scepticism, including because of negative Chinese reactions. Prime Minister Narendra Modi has called the Quad a force for global good. Among the Quad steps have been sharing vaccines during the Covid-19 pandemic, providing space-based maritime domain awareness data to Pacific Island countries to deal with climate, disaster forecasting, and illegal fishing, an Open RAN pilot in Palau, providing STEM fellowships, working on improving connectivity in the region. Measures have included practical cooperation on climate action, climate finance and technology transfer to countries to meet their climate commitments, addressing challenges of unsustainable debt financing. A Quad ASEAN Working Group has been established, and support for ASEAN centrality, and ASEAN-led regional architecture has been reiterated.

But they will be judged most by the benefits they bring to each other and their strategic interests. Six leader-level working groups have been set up on climate, critical and emerging technologies, cyber, health security, infrastructure, and space. They have reiterated calls for an open, secure, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient, and upholding the principles of sovereignty, territorial integrity and peaceful resolution of disputes. They have consulted on issues of maritime security, counter-terrorism, proliferation threats in Asia, resilience of supply chains including of critical minerals.

The relevance of Quad is also signified by the fact that subsequently, the ASEAN, the European Union, and several European countries have developed their own strategies and outlooks for the Indo-Pacific.

In the intense global contestation playing out between the US, Russia, and China, India has sought to maintain its strategic autonomy by making an effort to sustain the relationship with Russia and deepen the partnership with the US and its partners, and strengthen itself economically, technologically and in the defence domain through these choices. PM Modi is expected to participate in the BRICS summit being hosted in Russia in October. The Quad summit in September will reinforce the awareness of India's strategic options as it deals with its challenges and seeks to maximise its opportunities.

Arun K Singh is a former Indian ambassador to the United States. The views expressed are personal

Can Sheikh Hasina be extradited?

Why is Bangladesh's International Crimes Tribunal asking for the extradition of Ms. Hasina? Does the treaty signed in 2013 by India and Bangladesh allow for an extradition request to be turned down? What could be the potential implications of such a request?

EXPLAINER

Aaratrika Bhaumik

The story so far:

The chief prosecutor of Bangladesh's International Crimes Tribunal (ICT) has announced plans to seek the extradition of ousted leader Sheikh Hasina from neighbouring India. "As the main perpetrator has fled the country, we will start the legal procedure to bring her back," Mohammad Tajul Islam said on September 8. Ms. Hasina had sought refuge in India in August after a mass uprising compelled her to step down. Since her departure, numerous criminal cases have been lodged against her and her aides, encompassing charges of murder, torture, abduction, crimes against humanity, and genocide. Additionally, India and Bangladesh have a bilateral extradition treaty in place that could allow for her return to face trial.

What does the extradition treaty say?

The ICT was established in 2010 by Ms. Hasina to investigate crimes committed during the 1971 independence war from Pakistan. Under the International Crimes (Tribunals) Act of 1973, Bangladeshi courts can proceed with criminal trials even in Ms. Hasina's absence. However, this is bound to raise concerns about the fairness of the proceedings, and adherence to due process, while also complicating the enforcement of judicial orders. Therefore, the extradition of the former Prime Minister is crucial.

In 2013, India and Bangladesh signed an extradition treaty as a strategic measure to address insurgency and terrorism along their shared borders. It was amended in 2016 to ease the process of exchange of fugitives wanted by both nations. The treaty has facilitated the transfer of several notable political prisoners. For instance, in 2020, two convicts involved in the 1975 assassination of Ms. Hasina's father, Sheikh Mujibur Rahman, were extradited to Bangladesh for execution. Similarly, India successfully secured the extradition of Anup Chetia, the general secretary of the banned United Liberation Front of Assam (ULFA), who had spent 18 years imprisoned in Dhaka. The treaty mandates the extradition of individuals charged with or convicted of crimes that warrant a minimum sentence of one year's imprisonment. A key requirement for extradition is the principle of dual criminality, meaning that the offence must be punishable in both countries. Since the charges against Ms. Hasina are prosecutable in India, and the penalties for her alleged crimes are also substantial, she qualifies for extradition on these grounds. Additionally, the treaty encompasses within its ambit attempts to commit, as well as aid, abet, incite, or act as an accomplice in such crimes.

Forced departure: Bangladesh's former Prime Minister Sheikh Hasina in Dhaka on January 8. AFP

Notably, the 2016 amendment to the treaty substantially lowered the threshold for extradition by removing the requirement to furnish concrete evidence against the offender. Under Article 10 of the treaty, only an arrest warrant issued by a competent court in the requesting country is sufficient to initiate the extradition process.

Can extradition be refused?

Article 6 of the treaty stipulates that extradition may be refused if the offence is of a "political nature". However, there are stringent limitations on this particular exemption. A host of offences such as murder, terrorism-related crimes, and kidnapping, are explicitly excluded from being classified as political. Given that several of the charges against Ms. Hasina – such as murder and enforced disappearance– fall outside the scope of this exemption, it is unlikely that India will be able to justify them as political transgressions to deny extradition.

Another basis for refusal is outlined in Article 8, which permits denial of a request if the accusation is not "made in good faith in the interests of justice" or if it involves military offences not considered "an offence under general criminal law." India could potentially refuse extradition on the ground that the charges against Ms. Hasina have not been levelled in good faith and there is a possibility of her being subjected to political persecution or an unfair trial upon her return to Bangladesh. Such concerns are further exacerbated by recent reports that ministers from Ms. Hasina's cabinet were physically arrested by bystanders while being transported to court for remand hearings.

What are the potential implications?

Sreeradha Datta, professor of international relations at O.P. Jindal Global University told *The Hindu* that the treaty does not guarantee Ms. Hassina's extradition, as the final decision will hinge more on diplomatic negotiations and political considerations. "Even if India were to decline the extradition request, it would likely serve as a minor political irritant rather and is unlikely to dent bilateral relations, especially in critical areas of cooperation between the two nations," she said.

Bangladesh is India's largest trade partner in South Asia, with bilateral trade estimated at $15.9 billion in the fiscal year 2022-23. Before Ms. Hasina's ouster, both nations were poised to commence dialogue on a comprehensive economic partnership agreement (CEPA) to foster economic ties. Following the regime change in Dhaka, Indian Prime Minister Narendra Modi has spoken with the Chief Adviser of the new interim government, Muhammad Yunus, and pledged continued support for ongoing development projects.

THE GIST

- The chief prosecutor of Bangladesh's International Crimes Tribunal (ICT) has announced plans to seek the extradition of ousted leader Sheikh Hasina from neighbouring India.
- In 2013, India and Bangladesh signed an extradition treaty as a strategic measure to address insurgency and terrorism along their shared borders. It was amended in 2016 to ease the process of exchange of fugitives wanted by both nations. The treaty has facilitated the transfer of several notable political prisoners.
- Article 6 of the treaty stipulates that extradition may be refused if the offence is of a "political nature".